भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 345
मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़,1947 (शक) को उत्तरार्थ

डिजिटल मंचों से जुड़ी सहकारी समितियां

345. **श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड में ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए सहकारी समितियों को डिजिटल मंचों से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी पीएसीएस समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ग) क्या हरिद्वार जिले में दुग्ध संबंधी सहकारी समितियों को कोई सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भविष्य में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का विस्तार किए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
श्री अमित शाह

(क) से (ख): जी हाँ मान्यवर, उत्तराखंड में सहकारी समितियां डिजिटल परिवर्तन और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से व्यापक राष्ट्रीय पहलों का हिस्सा हैं, जिसमें एक कॉमन ईआरपी प्लेटफॉर्म पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण शामिल है, जिसे सहकारिता मंत्रालय की इस पहल के अंतर्गत, उत्तराखंड राज्य में 670 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को राष्ट्रीय पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में कम्प्यूटरीकरण के लिए चयन किया गया है । इस पहल का उद्देश्य सहकारी संस्थानों के डिजिटल एकीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना, सेवा प्रदान करने में सुधार करना और ग्रामीण विकास में तेजी लाना है । इन समितियों को नाबार्ड द्वारा विकसित ई-पैक्स सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है ।

दिनांक 30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार 670 पैक्स को कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर, यूपीएस और वीपीएन (कनेक्टिविटी डिवाइस) सहित हार्डवेयर उपलब्ध करा दिया गया है और सभी 670 पैक्स को ई-पैक्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP)) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है,

जिससे उनके मुख्य परिचालन का डिजिटलीकरण हो सके । उत्तराखंड में इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 13.48 करोड़ रुपये है ।

(ग): उत्तराखंड सहकारी डेयरी परिसंघ द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हरिद्वार जिले में 27 नई डेयरी सहकारी समिति स्थापित करने और 25 मौजूदा DCS को सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। राज्य दुग्ध विभाग दुग्ध सहकारी समितियों को दूध की गुणवत्ता जांच के लिए डेटा प्रसंस्करण युक्त दुग्ध संग्रहण इकाइयाँ उपलब्ध करा रहा है ।

(घ): जी हाँ मान्यवर। सरकार ने दिनांक 15.2.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करने की योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना में पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स (एम-पैक्स), डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है । यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा । वर्तमान में सभी 672 पैक्स बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां बन गई हैं, ताकि सभी MPACS विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों जैसे CSC केंद्र, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र आदि का संचालन कर सकें । इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की "2 लाख नई MPACS/ डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों के गठन" पहल के अंतर्गत 587 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (MPACS) का गठन भी किया गया है । ये सभी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (MPACS) अपनी वित्तीय स्थिति को सशक्त करने और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अपनी उपविधियों के अनुसार अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का विस्तार कर सकते हैं ।

*****